MEERUT CITIZENS FORUM

अंक 1 / फरवरी-मार्च 2021

जन संवाद

मेरठ में बेहतर जीवन स्तर के लिए

नगर आयुक्त श्री मनीष बंसल (आई0ए0एस0) के साथ मेरठ सिटीजन फोरम के सदस्यो की बैठक।

फोरम द्वारा दिनांक 12.01.2021 में नगर आयुक्त के साथ की गई चर्चा के बिन्दु नगरीय सेवा में सुधार के इर्द–गिर्द रहे। निम्न बिन्दुओ पर विस्तृत चर्चा की गयी।

1. नगर निगम में ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था विकसित करना।
2. प्रबन्धन सूचना तन्त्र विकसित करना।
3. निगम कर्मचारियो/अधिकारियो की कार्य क्षमता वर्धन की कार्य योजना तैयार करना।
4. बेहतर ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के लिए घर–घर से कूडा एकत्रीकरण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए अपशिष्ठ उत्पादको के दायित्वो के प्रति जागरूकता के लिए बाहय संस्था की सहायता लेने की आवश्यकता, कूडा घरो को समाप्त करने के लिए विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिंग यूनिटस की स्थापना कर नगरीय ठोस अपिशष्ठ की मात्रा घटाना।
5. पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ण गंगा. जल का उपयोग कर भूगर्भ से टयूबवैल्स द्वारा अनावश्यक जलदोहन को बंद करना।

6. नगर निगम की आय में वृद्धि कर स्वावलम्बी बनाना। फोरम द्वारा प्रस्तुत किये गये बिन्दु पर नगर आयुक्त द्वारा सहमति व्यक्त करने के साथ–साथ कुछ बिन्दुओ को लागू करने में आ रही बाधाओ का उल्लेख किया।

जिलाधिकारी श्री के0 बालाजी (आई0ए0एस0) के साथ फोरम के शिष्ठ मण्डल की बैठक।

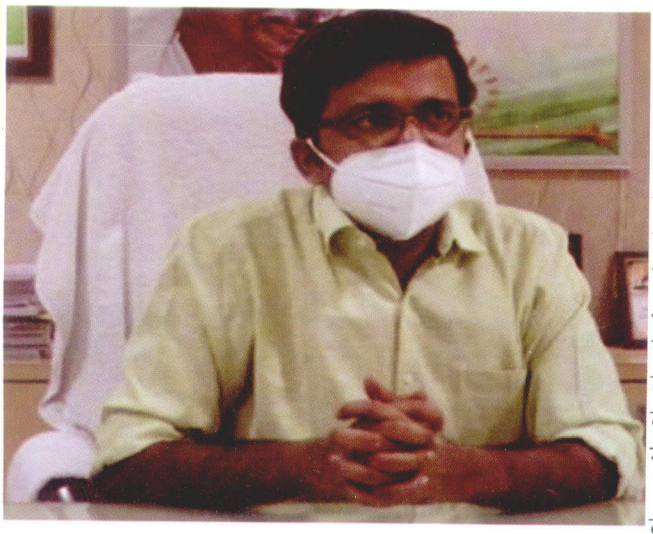

नगर में नवनियुक्त जिलाधिकारी की सक्रियता को देखते हुए, फोरम के एक शिष्ट मण्डल द्वारा कैम्प कार्यालय में दिनांक 28.10.2020 को एक बैठक की गयी व मेरठ से सम्बन्धित योजनाओ जैसे 1. कूडा प्रबन्धन 2. नगर की 100 एम0एल0डी0 गंगा जल योजना 3. जलशक्ति अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य 4. नगर निगम में एनर्जी ऑडिट लागू कराना। उपरोक्त विषयक प्रस्तुत कर योजनाओ की ओर जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित किया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ बिन्दुओ पर जिज्ञासा सहित फोरम सदस्यो के साथ चर्चा की।

भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के मेरठ में नोडल अधिकारी श्री प्रदीप कुमार के साथ बैठक करते हुए मेरठ सिटीजन फोरम के प्रतिनिधि।

भूजल सप्ताह दिनांक 27.07.2019 को मुख्य विकास अधिकारी, ईशा दोहन (आई0ए0एस0) के साथ बैठक करते हुए मेरठ सिटीजन फोरम के शिष्ठ।

इंदौर मॉडल पर होगी मेरठ के पांच वार्डों में सफाई

अन्य नगरो की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियो को मेरठ नगर में अपनाने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान में इंदौर की कहानी से प्रेरित हो कर वहाँ की कार्यदायीसंस्था मै0 बैसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट वेंचर्स से 10 लोगो की एक टीम बुला कर नगर निगम की सहमति से 50 हजार की आबादी वाले 5 वार्ड में तीन माह के लिए एक डेमो प्रोजेक्ट चलाया गया। इसका समस्त व्यय भार फोरम द्वारा वहन किया गया। माननीय श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने प्रोजेक्ट क्षेत्र में भ्रमण किया गया। दिल्ली दूरदर्शन द्वारा भी इसका प्रसारण किया गया।

उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नीति का एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशन

भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम 2000 को संशोधित कर दिनांक 8 अप्रैल 2016 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नीति दिनांक 29 जून 2018 जारी की गयी। इस नीति के प्रचार–प्रसार और स्वच्छता के प्रति हिस्सेदारो में जागरूकता पैदा करने के लिए फोरम द्वारा इस नीति को एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया। पुस्तिका का विमोचन आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा दिनांक 10.08.18 में किया गया। पुस्तिका की प्रतिलिपियां सम्बन्धित विभागो, नगर निगम पार्षदो व अन्य सभी जनप्रतिनिधियो में वितरित की गयी।

"मेरठ के विकास के मुद्दे उनसे जुडी चुनौतियां एवं समाधान" विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन दिनांक 5 दिसम्बर 2017

बेहतर जीवन स्तर के लिए मेरठ नगर में जनसुविधाओ की मांग व आपूर्ति में अन्तर को पाटने के लिए शासन द्वारा समय–समय पर अनेक परियोजनाये तैयार की, परन्तु इनमें से काफी योजनाये पूर्ण नही हो सकी। इन्ही विचारो को दृष्टिगत रखते हुए फोरम द्वारा मेरठ के विकास के मुद्दे उनसे जुडी चुनौतिया एवं समाधान विषय पर दिनांक 5 दिसम्बर 2017 को एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसका उदघाटन आदरणीय सांसद श्री राजेन्द्र अग्रवाल (हापुड, मेरठ) माननीय आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा किया गया। आयोजन में प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, नगर आयुक्त के साथ–साथ बैंगलोर संस्था जनाग्रह, बैसिक्स हैदराबाद व फिशमे के प्रतिनिधि की भागीदारी रही। सम्मेलन में फोरम के अध्यक्ष श्री विवेक सिंघल द्वारा सभी अगुन्तको का स्वागत किया तथा सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथियो द्वारा मोबाईल आधारित नागरिक शिकायतो के दो एप्प "आईचेंज माई सिटी एवं सिविक आई" लॉन्च किये गये। बाद के सत्रो में मोबिलिटी और स्वच्छता से सम्बन्धित चुनौतियां एवं उनके समाधान पर विभिन्न वक्ताओ द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किये। समापन सत्र में प्रबन्ध निदेशक पावर कॉरपोरेशन द्वारा नगर के विकास पर अपने विचार रखे।

"If I were Mayor of Meerut" के विजेताओ को पुरस्कृत किया गया।

स्थानीय निकाय प्रशासन में जनप्रतिनिधियो की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्ही दायित्वो के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अक्टूबर 2017 में "If I were Mayor of Meerut" निबन्ध की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओ को नकद इनाम प्रबन्ध निदेशक पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किया गया।

dated-23.02.20 Hindustan

पानी पिलाने के नाम पर 10 करोड़ का गोलमाल

dated 23.02.20 Amar Ujala

'गंगाजल न मिलने पर हो रहा शहर का भूगर्भ जल दोहन'

दिनांक - 13.10.20 अमर उजाला

तीन साल बाद भी हैंडओवर नहीं हुआ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

400 करोड़ के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जेब भरने का मामला

दिनांक - 18.10.20 अमर उजाला

सांसद ने किया प्लांट का निरीक्षण

मेरठ। भोला झाल स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की खामियां उजागर होने के बाद शनिवार को सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने प्लांट का निरीक्षण किया। मौके पर मिली अव्यवस्थाएं और प्लांट को पूरी क्षमता से न चलाए जाने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। शहर को गंगाजल सप्लाई करने के लिए भोलाझाल पर 100 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। नगर निगम ने जल निगम को इसके संचालन का जिम्मा सौंपा है। अमर उजाला ने ट्रीटमेंट प्लांट की खामियों पर खबरें प्रकाशित की।

Citizen Charter
Municipal Corporation Meerut
Applicable w.e.f. 21.09.2010

Contact Us @

Municipal Commissioner
Nagar Nigam Meerut
Kesarganj, Meerut – 250002
Ph No: 0121-2515133
Fax No: 0121 - 2665809
E-mail: nnmee@up.nic.in

मेरठ नगर निगम दिनांक 21.09.2010 से सिटीजन चार्ट प्रभावी है। नगर निगम से अनुरोध किया गया है कि, आम नागरिको की जानकारी हेतु समुचित प्रचार–प्रसार किया जाए, जिससे नागरिक अधिकारी के साथ समय सीमा में सुविधा प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विभागो पर दवाब बना सके।

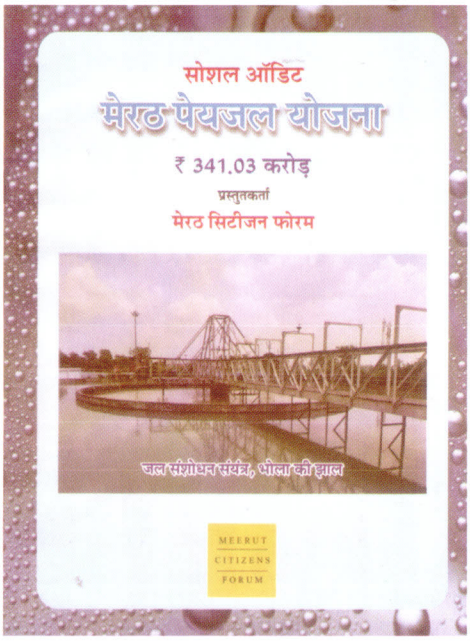

मेरठ पेयजल योजना रू0 341 करोड

मेरठ नगर के गिरते भूजल स्तर की भयावह स्थिति को देखते हुए, भूभृत से अनावश्यक जल दोहन को बंद करने के दृष्टिकोण से यह अति आवश्यक समझा गया कि, नगर निगम को उपलब्ध 100 एम0एल0डी0 गंगाजल को शतप्रतिशत उपयोग कर गंगाजल के अच्छादित क्षेत्र में बडी संख्या में लगे टयूबवैल से भूगर्भ जल का दोहन बंद करना। इस सम्बन्ध में नगर निगम से निरन्तर पत्राचार किया गया। निरन्तर प्रयास के उपरान्त भी सफलता न मिलने पर मेरठ नगर की पेयजल योजना रू0 341 करोड वर्ष 2008–09 का फोरम द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया एवं स्थलीय निरीक्षण भी किये गये। इसका एक विस्तृत विशलेषण/सॉशल ऑडिट तैयार किया गया जिसे माननीय सांसद श्री राजेन्द्र अग्रवाल की अध्यक्षता में नगर निगम व जल निगम के अधिकारियो के साथ दिनांक 09.09.19 में बैठक कर प्रस्तुत किया गया। दोनो विभागो द्वारा विशलेषण पर सहमति व्यक्त की गयी तथा त्वरित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया। इस विशलेषण में पेयजल योजना में निर्मित अनेक संरचनओ को उपयोग में नही लिया जा रहा है। फोरम का स्पष्ट मत है कि, ये सार्वजनिक धन के साथ खिलवाड़ है। योजना का विशलेषण एक लघु पूस्तिका के रूप में जन सामान्य के लिए प्रस्तुत किया गया।

@MrtNagarNigam

मेरा मेरठ बनेगा नं0 1

मेरठ शहर को फीडबैक देने के लिए
SS2021
(Vote For Your City)
एप डाउनलोड करें।

भूजल संकट का समाधान (संक्षिप्त में)

वर्षा जल संचयन

↓

संचयित वर्षा जल को भूगर्भ में भेजना

↓

नगर के प्राकृतिक जल संचयन श्रोतों का जिर्णोद्धार

↓

पेड़ पौधों, पार्कों, हरित पट्टी आदि की सिचाई में, साफ पानी के स्थान पर शोधित सीवर जल का उपयोग

↓

भवनों में कम जल प्रयोग करने वाले साजो–सामान का उपयोग

वर्षा जल का सदुपयोग

वर्षा जल एक अनमोल प्राकृतिक उपहार हैं, जो प्रतिवर्ष पृथ्वी को बिना किसी भेद भाव के मिलता रहता हैं। समुचित प्रबंधन के आभाव में वर्षा जल व्यर्थ नदीं नालों से बहता हुआ समुंद्र के खारे पानी से मिल जाता हैं। मेरठ के परिपेक्ष में भूजल संकट को दूर करने के लिए वर्षा जल का संग्रहण व उसे भूभृत में भेजना ही वर्तमान में एक विकल्प हैं।

Public interest Litigation
No. 1858 of 2020
Before
Hon'ble High Court
Allahabad
Petitioner Meerut Citizens Forum
Respondent State of U.P
and
7 others

That the present public interest litigation has been filed on issues relating to the city of Meerut, which are as follows:

a) **ISSUE I:** Critical situation of the city with respect to management of solid waste.

b) **ISSUE II:** Non-cleansing and resultant choking of all storm drains and sewerage drains alike.

c) **ISSUE III:** Non-functional Sewage Treatment Plants and Water Treatment Plants.

d) **ISSUE IV:** Large amount of air pollution caused by uncontrolled burning of solid waste.

e) **ISSUE V:** Unregulated and excessive Ground Water extraction through tube-wells by the authorities and pollution of ground water.

f) **ISSUE VI:** Non-utilisation of available reservoirs and tanks for the purposes of water supply to the city.

g) **ISSUE VII:** Appointment of an Environmental Engineer and other qualified IAS officers in the Municipality, who have scientific temper and are better-equipped to deal with issues related to civic amenities like sanitation and environment.

Hon'ble Govind Mathur, C. J.
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery, J.
PIL Admitted
respondents allowed time
to file - "counter affidavit"
Order dated 11.1.2011

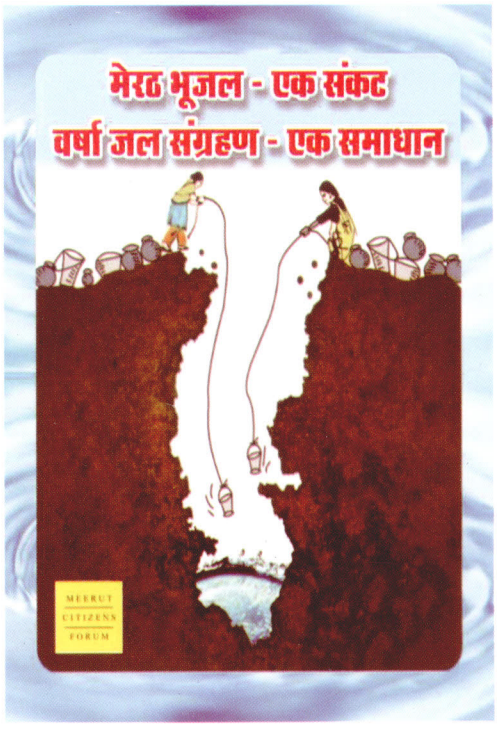

मेरठ में गिरते भूजल स्तर का समाधान

के जून 2019 में विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र की रिपोर्ट पर आधारित समाचार "कि मेरठ सहित अन्य 21 शहर भूगर्भ जल के दृष्टिकोण से संकट ग्रस्त है अर्थात "वर्ष 2030 तक भूगर्भ जल समाप्त के कगार पर है"। इस भयावह स्थिति से उभरने लिए फोरम द्वारा गम्भीरता से चिन्तन किया गया और मेरठ के परिपेक्ष में विभिन्न स्थानो पर भूजल की गहराई, वर्षा की अवधि एवं तीव्रता का अध्ययन किया गया, साथ ही भवनो की छत से वर्षा के संचयन तथा भूगर्भ में पुर्न भरण के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, जल संस्थान मंत्रालय के मार्ग दर्शक सिद्धान्तो का अध्ययन किया गया तथा इस गम्भीर समस्या के प्रति जन–सामान्य को जागरूक करने के लिए "मेरठ भूजल–एक संकट, वर्षा जल संग्रहण–एक समाधान" नामक एक लधु पुस्तिका प्रकाशित की गयी, इसका विमोचन माननीय सांसद श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा दिनांक 23.06.2019 में किया गया। इसकी प्रतिलिपियां सम्बन्धित विभागो और नगर निगम सहित सभी जनप्रतिनिधियो को निशुल्क वितरित की गयी, तथा फोरम की सलाह पर आधारित नगर के अनेको स्थानो पर वर्षा जल संचयन कर भूभृत में संरचना कराई गयी।

मेरठ भूजल एक संकट वर्षा जल संग्रहण एक समाधान

लघु पुस्तिका का विमोचन करते हुए मां0 सांसद राजेन्द्र अग्रवाल जी

MEERUT CITIZENS FORUM
A 211 SAKET MEERUT U.P. 250001

info@meerutcitizens.in / @meerutcitizens /
meerutcitizens / www.meerutcitizens.in